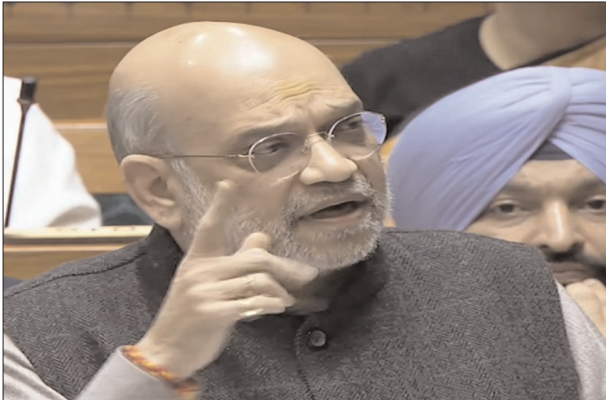


वोट चोरी का फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा विपक्ष: अमित शाह

निर्वाचन आयोग को वोट चोरी करने का हथियार बना रही है भाजपा : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी समेत विपक्षी सदस्यों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ नेता विभिन्न राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर महीनों से झूठ फैलाया जा रहा है और सभी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी भी एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने के लिए 'वोट चोरी' का नारा गढ़ रहे हैं। शाह ने कहा कि दो दिनों तक

हमने विपक्ष से कहा कि इस पर दो सत्रों के बाद चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन वे नहीं माने। हम मान गए... हमने 'ना' क्यों कहा? 'ना' कहने के दो कारण थे। पहला, वे (एसआईआर) पर चर्चा करना चाहते थे। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती। एसआईआर आयोग की जिम्मेदारी है। भारत का चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करते। अगर चर्चा हुई और सवाल उठाए गए, तो उनका जवाब कौन देगा? जब उन्होंने कहा कि वे चुनावी सुधारों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो हम तुरंत सहमत हो गए।



अमित शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा को लेकर पहले दो दिन तक गतिरोध बना रहा। इससे जनता को गलत संदेश गया कि हम इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। मैं यह स्पष्ट

करना चाहता हूं कि संसद इस देश में चर्चाओं की सबसे बड़ी पंचायत है। भाजपा-एनडीए कभी भी चर्चाओं से पीछे नहीं हटती। विषय चाहे जो भी हो, हम संसद के नियमों के अनुसार

चर्चा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चार महीनों तक एसआईआर के बारे में एकतरफा झूठ फैलाया गया। देश की जनता को गुमराह करने के प्रयास किए गए। शाह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब चुनाव जीतते हैं तो मतदाता सूची अच्छी है और जब हारते हैं तो मतदाता सूची खराब है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पहला एसआईआर (चुनाव सर्वेक्षण) 1952 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में किया गया था और फिर कहा कि नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकारों सहित कांग्रेस सरकारों के दौरान कई एसआईआर हुए।



आइडिया ऑफ इंडिया (भारत की अवधारणा) नष्ट कर रही है। उन्होंने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान 2023 के निर्वाचन कानून का उल्लेख करते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस कानून में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा तथा चुनाव आयुक्तों को कठघरे में लिया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि 2023 के इस कानून को बदलने की जरूरत

है क्योंकि यह निर्वाचन आयुक्तों को यह ताकत देता है कि वे जो चाहें करें। उन्होंने कहा था कि इसकी चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा-शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल, बच्चों की छुट्टी कराकर जांच में जुटी टीमें

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर। राजधानी में दो स्कूलों को दिन में पहले बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलने के बाद, बुधवार को संस्कृति स्कूल को भी इसी तरह का एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें खालिस्तान आंदोलन का जिक्र था। संदेश में लिखा था, आज दोपहर 12:05 बजे बम धमाका होगा? झूठी पुलिस मुकाबला करके पंजाब में खालिस्तान जनमत संग्रह करवा दें, खालिस्तान आंदोलन को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र तक ले जाएं। अधिकारी इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं और स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आज सुबह, स्कूलों ने एहतियात के तौर पर अभिभावकों को अपने बच्चों को लेने के लिए तुरंत एक सूचना जारी की। सूचना में छात्रों



सुबह 9:45 बजे, कक्षा 6 से 8: सुबह 9:55 बजे, कक्षा 9 और उससे ऊपर: सुबह 10:15 बजे।

इसी समय, नई दिल्ली स्थित अहल्कोन इंटरनेशनल स्कूल को भी बम की धमकी मिली। स्कूल ने भी अभिभावकों को इसी तरह का एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें छात्रों को सुरक्षित और समय पर ले जाने के लिए वैन चालकों के साथ समन्वय करने की सलाह दी गई। नोटिस में कहा गया कि प्रिय अभिभावक, कृपया ध्यान दें कि आज सुबह प्राप्त एक ईमेल धमकी के कारण, हम अपने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सभी छात्रों (फुटबोर्ड/बस/वैन) के लिए सुबह 11:30 बजे जल्दी स्कूल छोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं।

सुरेश गांधी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने बुधवार को वर्चुअल संबोधन के दौरान साइबर सुरक्षा पर बढ़ते खतरों को लेकर सावधान किया। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद से लोगों की डिजिटल निर्भरता, फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और इंटरनेट उपयोग, अभूतपूर्व रूप से बढ़ी है। भारत में डेटा सस्ता होने के कारण उसका उपयोग विकसित देशों की तुलना में 70 गुना अधिक है, लेकिन यही सुविधा साइबर अपराधियों के लिए बड़ा अवसर बन चुकी है। डीजीपी ने स्पष्ट कहा कि लोभ,



लापरवाही, डिजिटल लत और मनोवैज्ञानिक भय (डिजिटल अरेस्ट) साइबर अपराध का शिकार बनने के चार प्रमुख कारण हैं। उन्होंने हार्डिजिटल अरेस्ट जैसे नए साइबर फ्रॉड से सावधान करते हुए

बताया कि किसी भी भारतीय कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं है। ऐसे कॉल, वीडियो कॉल या संदेश पूरी तरह धोखाधड़ी हैं। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि साइबर

अपराध होने पर हंगोलडन आवरहू के अंदर सटीक सूचना देना बहुत जरूरी है। इसी तेज प्रतिक्रिया के कारण पिछले तीन महीनों में 130 करोड़ रुपये की रकम पीड़ितों को लौटाई जा सकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में साइबर थाने तथा 1576 थानों पर साइबर हेल्प डेस्क सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। डीजीपी ने अपील की कि हूआज का सहभागी आगे 100 लोगों को जागरूक करे, क्योंकि जागरूकता ही साइबर अपराध के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। कार्यशाला में पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल ने बताया कि कमिश्नरी ने साइबर

अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। इसके तहत : 5 फर्जी कॉल सेंटरों पर कार्रवाई, 75 साइबर अपराधी गिरफ्तार 1400 संदिग्ध मोबाइल नंबर ब्लॉक पीडितों के 7.5 करोड़ रुपये वापस कराए गए फर्जी सिम बेचने वाले 8 लोगों को जेल भेजा गया 600 से अधिक साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित आसान भाषा में तैयार हासाइबर ज्ञान पुस्तिकाहू की 50,000 प्रतियाँ जनता में वितरित पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर अपराध रोकने में जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है, और वाराणसी पुलिस इस दिशा में व्यापक अभियान चला रही है।

105वां दीक्षांत : बीएचयू में ज्ञान, गौरव, मेधा और नई उड़ान का महोत्सव

वाराणसी। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय 12 दिसंबर को अपना ऐतिहासिक 105वां दीक्षांत समारोह भव्यता और गरिमा के साथ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश - विदेश में अपनी शिक्षण परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के लिए पहचाने जाने वाले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस बार भी हजारों विद्यार्थियों के जीवन में एक सुनहरी याद बनकर दर्ज होने जा रहा है। इस वर्ष कुल 13,650 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। जबकि 555 मेधावी छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल और सम्मान से नवाजा जाएगा। मुख्य समारोह स्वतंत्रता भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि मुख्य समारोह में 29 मेधावी विद्यार्थियों को 2 चांसलर मेडल, 2 स्वर्णीय महाराजा



विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक, तथा 29 बीएचयू पदक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दीक्षांत केवल औपचारिकता नहीं, जीवन की नई यात्रा का प्रारंभ है। कुलपति ने बताया कि बीएचयू विद्यार्थियों को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि उन्हें चरित्रवान, संवेदनशील और नैतिक मूल्यों से युक्त नागरिक भी बनाता है। उन्होंने सभी छात्रों से पुराछात्र पोर्टल से जुड़कर विश्वविद्यालय परिवार के साथ संबंध बनाए रखने का आग्रह किया। कुलपति ने बताया कि यह समारोह विद्यार्थियों, शिक्षकों

और अभिभावकों के लिए ह्रसमर्पण का पर्वहू है, एक ऐसा क्षण जब

सालभर की कठोर मेहनत और संघर्ष, सफलता और उपलब्धियों की रोशनी में बदल जाते हैं। इस बार दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगे डॉ. विजय कुमार सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग, जेएनयू के कुलाधिपति और देश के प्रतिष्ठित रक्षा वैज्ञानिक, डॉ. सारस्वत : भारत के स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और कई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशनों के प्रमुख मार्गदर्शक रहे हैं।

आर के मीडिया
हिन्दी दैनिक न्यूज पेपर, साप्ताहिक न्यूज पेपर, हिन्दी मासिक पत्रिका का पेज बनवाने के लिए सम्पर्क करें: 9199355950

भाई की हत्या के दोषी व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटे को उम्रकैद
बलिया। बलिया की एक स्थानीय न्यायालय ने जमीन के विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या के चार साल पुराने मामले में मृतक के सगे भाई और उसकी पत्नी तथा बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी पी. एन. स्वामी ने बुधवार को बताया कि जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के रतसड़ खुर्द नामक गांव में गत 19 जुलाई 2021 की रात छद्म वर्मा नामक व्यक्ति की जमीन के विवाद को लेकर उसके सगे भाई किशुन वर्मा, उसकी पत्नी उषा तथा किशुन के पुत्र अमृत एवं अमित ने लाठी-डंडे और ईंट से प्रहार करके हत्या कर दी थी।



मोहम्मद दानिश
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड नं० 10
के भावी प्रत्याशी



NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE

ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

वंदे मातरम् आन्दोलन मठ के सताना द्वारा गया जान वाला गाँव है। वंदे देशभक्ति के धर्म के प्रतीक के रूप में खड़ा था, जो आन्दोलन को केंद्रीय विषय था। अपने मर्म में, उन्होंने मातृभूमि का प्रतिनिधित्व करने वाली माँ की तैयारी मूर्तियाँ स्थापित कीं। वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी (1838-1894) 19 वीं सदी के बंगाल के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उनकी उत्तमसर्वी सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार, सावित्री और निबंधकार के रूप में, उनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। आनंदमठ (1882), दुर्गेशनंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866) और देवी चोधराजी (1884) सहित उनकी उल्लेखनीय रचनाएँ, आत्म-पहचान के लिए प्रयासरत एक उपनिवेशित समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दर्शाती हैं। वंदे मातरम् की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में एक मील का पथर माना जाता है, जो मातृभूमि के प्रति समर्पण और आध्यात्मिक आदर्शवाद के संश्लेषण का प्रतीक है। वंदे मातरम् में उन्होंने देश को मातृभूमि के दर्शन कराया, जिससे माता का रूप दिया गया। अक्टूबर 1905 में, मातृभूमि को एक मिशन और धार्मिक जुनून के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्तरी कोलकाता में एक वंदे मातरम्-संप्रदाय की स्थापना की गई थी। हर रविवार को, समाज के सदस्य प्रथा फेरी निकालते थे, वंदे मातरम् गाते थे और मातृभूमि के समर्पण में लोगों से स्वीच्छक योगदान स्वीकार करते थे। रवींद्रनाथ टैगोर भी कभी-कभी कभी संप्रदाय की प्रभात फेरी में शामिल होते थे। 20 मई 1906 को, बारीसाल (अब बांग्लादेश में) में, एक अभूतपूर्व वंदे मातरम् जुलूस निकाला। इसमें सस्तर हजार से अधिक प्रतिभागियों, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था। इतिहास गवाह है कि जिन्ना को खुश करने के लिए पं. जवाहर लाल नेहरू ने उनकी अपावृत्ति के उत्तर में लिखा था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् को कभी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार नहीं किया, जबकि सत्य यह है कि आन्दोलन के संन्यासी भगवान् की तरह आज भी देशप्रेमियों के रागों में वंदे मातरम् गीत उबाले ला देता है और माँ भूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। जिस देश के पीछे न जाने कितनी माँ की गोद सूनी हो गई, कितनी महिलाओं की मांग के सिंदूर धुल गए, बंग-भंग आन्दोलन के समय जो गीत धरती से आकाश तक गुँज गए, बंगाल की खाड़ी से जिसकी लहरें इंगलिश चैनल पर का ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गईं, जिस गीत के कारण बंगाल का बंटवारा नहीं हो सका, उसी गीत को अल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए खंडित किया गया। यहां तक कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए मातृभूमि को खंडित किया गया। उसके बाद भी जनमानस को उद्धित करने वाले इस गीत को प्रमुख राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आज संसार में वंदेमातरम् को लेकर जो खींचतान हो रही है वह भी वंदेमातरम् की गरिमा से खिलवाड़ ही है।

12 अरब डॉलर के पकेज की घोषणा इसी संदर्भ में हुई है। ट्रांस्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कहा, हबम टैरिफ से मिली आय का एक छोटा हिस्सा किसानों के लिए आर्थिक सहायता के रूप में दे रहे हैं। हम अपने किसानों से प्यार करते हैं। हम इसमें से 11 अरब डॉलर नए 'फार्म ब्रिज ऑसिटेस' कार्यक्रम के तहत रोर क्रॉप किसानों (जैसे सोयाबीन उत्पादक) को दिए जाएंगे जो व्यापार विवादों और बढ़ती लागतों से प्रभावित हैं। शेष एक अरब डॉलर के आवंटन पर अभी विचार चल रहा है। इस साल किसानों को पहले ही आपदा राहत और आर्थिक सहायता के रूप में 4 अरब डॉलर की सॉफ्टडी मिल चुकी है।

दूसरा और सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग का इस मामले पर मजबूत रुख है। उनका कहना है कि बैलेट पेपर वे जमाने में चुनावों में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और हिंसा होती थी। उस सत्ता दम्बण अपने इलाकों में जबरन बैलेट पेपर डालकर चुनाव परिणामों का प्रभावित करते थे। मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक पहुँचने से रोका जाता था, धमकियाँ दी जाती थीं और कागज बार मापीष्ट ही होती थी। बैलेट पेपर के डिब्बों में स्याही या पानी डालकर मतदाता का अधिकार छीना जाता था। ऐसी स्थिति में लोकतन्त्र को पराकाष्ठा नहीं को खतरा था और जनता की मंशा का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता था। इन्हीं कारणों से चुनाव आयोग ने बहुसंख्य-विचार के बाद ईवीएम अर्थात् सोल्वेटॉनिक वोटिंग मशीन का अपनाया। इसके अन्तर्ग के बाद चुनाव प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, त्वरित और पारदर्शी हुई है। चुनाव आयोग बार बार यह स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। संवैधानिक दिशा-निर्देशों के तहत

2025 के दौरान रव्दी मातरम् की 150वीं वर्षांठ मानने के लिए एक विशेष चर्चा आयोजित की गयी। गौरव तिलक है कि संस्कृत और बालांला भाषा के मिश्रण से तैयार किया गया यद्य गीत पहली बार 1882 में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित उनकी बालांला उपन्यास आनंदमठ में प्रकाशित हुआ। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने इसी गीत अर्थात रचनेवाला मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आर्य देश में इस गीत को ही राष्ट्रनाम अर्थात रजन गमर के ही समकक्ष सम्मान प्राप्त है। सभी सरकारी औपचारिक कार्यक्रमों में जब इसे गाया या बजाया जाता है, तो सभी लोग इसके सम्मान में खड़े होते हैं। परन्तु हमारे देश के में मुस्लिम उपलगा को एक पैसा है। जिनका मानना है कि धरती-माँ को इस तरह देवी के रूप में पूजा और उसके सम्मान से सजदा करना इस्लाम विरोधी (शिर्क) है। और अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना हाराम है।

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का इलजाम लगाया रहती है। यही कोशिश गढ़ दिनों संसाधन में हर्द्वे मातरम पर चर्चा के दौरान देखने को भी मिली। खासकर इस चर्चा का ऐसे समय में होना जबकि आगामी वर्ष बंगाल में चुनाव भी प्रस्तावित हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों की तर्फ इशारा करता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में हर्द्वे मातरम पर बहस के दौरान सरकार पर तीखा गहरा करते हुए यही कहा भी कि राष्ट्रगान पर बहस को

इसलिए लग रहा है चूँकि भारत में चावल पैदा करने की लागत दुनिया में सबसे कम है झ एक टन गैर-बासमती चावल की लागत मात्र 15-18 हजार रुपये (लगभग 180-220 डॉलर) पड़ती है, जबकि अमेरिका में यही लागत 38-45 हजार रुपये (450-550 डॉलर)

हलाकि, विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बजाय प्रचार-प्रसार और सार्वजनिक मंचों पर ही वोट चोरी का आरोप लगाना जारी रखा है। राहुल गांधी के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों के नेता भी ईवीएम की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह तकनीक शक्तिशाली दलों का पक्ष लेती है। वे दावा करते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर ईवीएम के माध्यम से सत्तासीन पार्टी का समर्थन

दरअसल विश्व व्यापार संगठन
क निर्यात में डीपिंग की भी अवैध मानी
जाती है जब आयात करने वाला देश
माबित कर दे कि (1) निर्यात मूल्य
रेलू मूल्य या उत्पादन लागत से कम
(2), इससे स्थानीय उद्योग को
नारी नुकसान हो रहा है, और (3)
नुकसान का सीधा कारण वही
तस्ता आयात है। अमेरिका ने
हले भी भारत के चावल पर एंटी-
डीपिंग जांच शुरू की है, लेकिन
व्यादातर मामलों में भारत बच
जाता है क्योंकि टूटा चावल की
रेलू कीमत तुलना करना मुश्किल
है और भारत कहता है कि
मारी सप्लिडी किसानों के लिए
निर्यात के लिए नहीं। फिर भी
2025 में अमेरिकी किसानों का
रसा इतना बढ़ गया है कि टुप ने
ए टैरिफ लगाने की धमकी दी है।
वही वजह है कि इसे रचावल
डीपिंग का मामला कहा जा रहा
हय घटनाक्रम वैश्विक व्यापार
न अनिश्चिता को बढ़ा रहा है,
वासकर कृषि क्षेत्र में। विशेषज्ञों
का कहना है कि टुप की 'अमेरिका
नस्ट' नीति से न केवल विदेशी

उन्होंने कहा कि भारतीय
चाल के लिए स्थिर बनी हुई है
परन्तु को मांग अमेरिका कोई
बिना बाजार नहीं है। इसके अलावा
भारतीय निर्यातकों को नए और
नए वैश्विक बाजारों से अच्छी
मिल रही है, जिससे समग्र
भारत बास्केट मजबूत बनी हुई है।
कोई यह टिप्पणी वाशिंगटन में
भारत के निर्यातों पर अतिरिक्त शुल्क
नियमों पर चर्चा के बीच आई है,
जिन पर पहले से ही 50 प्रतिशत
पर लगाया है। गर्ग ने कहा कि छह
महीने पहले 10 प्रतिशत से शुरू
कर यह शुल्क 25 प्रतिशत और

पिछले तीन महीनों में भारत तक बढ़ गया है। इसका कारण यह है कि प्रभाव नहीं पड़ा है। उद्योगिक निष्कर्षों में नियात पिछले वर्ष के समान रही है। उद्योगिक निष्कर्षों में न कहा कि शुल्क में भी वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों द्वारा वहन की जा रही है। मिला समूह के सीईओ विलेवॉल ने कहा कि अमेरिकी निर्यात की जाने वाली भारत-बासी प्रीमियम गैर-बासी में एशियाई और मध्य एशियाई के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों का कहा कि ये आवश्यक हैं, विलासिता की आवश्यकताएं हैं। मांग पर प्रभाव नगण्य है। निर्यात की अतिरिक्त शुल्क में वृद्धि के कारण केवल अमेरिकी निर्यातकों को ही भुगतान पड़ेगा, जो वैश्विक चालन निर्यात प्रभावित आपूर्ति करता है। 2 देशों को नियात करता है। भारत पर मजबूत मांग देखी जा रही है। खाड़ी देश बासमती के प्रभाव से हुए हैं, वहीं अफ्रीकी देशों में बढ़ते खरीदार के रूप में हैं। उदाहरण के लिए, वेनेजुएला साल 60,000 टन बासमती का आयात किया है। न कहा कि यह एक नया बंधन है। बहुत तेजी से विस्तार करने में भी गैर-बासमती निर्यात अपने पारंपरिक प्रोसेस से तेज हुए बासमती की खरीद कर रहे हैं। उन्हीं का कहा कि ब्राजिल जैसे प्रमुख चालक देश भी भारतीय बासमती आयात कर रहे हैं। गर्ग ने भारत की को पड़े छोड़ दिया। या का सबसे बड़ा बासमती बासमती बन गया है और उन्हीं घरेलू उत्पादन में 4-5 प्रतिशत वृद्धि होने को संभावना है। निर्यातकों को बेहतर मूल्य मिल

इस पूरे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग सिस्टम की समीक्षा और सुधार आवश्यक है, अगर इसे वैज्ञानिक आधार और स्थलात्मक प्रमाणों के आधार पर करना चाहिए। वे कहते हैं कि बिना किसी मतदान सबूत के, वोटिंग मशीन पर निर्भार लगाना लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसके बजाय सभी राजनीतिक दलों को साथ मिलकर चुनाव सुधारों पर विचार करना चाहिए और मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखना चाहिए। चुनाव आयोग ने पुनर्निर्धारित मतदाता पहचान प्रक्रिया, ईडोएम के सुरक्षा तंत्रों को नवीनतम तकनीक, वीवीपैट की पूर्ण जांच और चुनाव कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार जैसे कई कदम उठाए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पर कोई

योग ने अन्धविश्वास चुनाव कराने के लिए प्रयत्न किया। अन्धविश्वास तकनीकों को अपनाने की विचार किया है जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत नहीं करती। राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस और महागठबंधन इस मुद्दे को ध्यान में रखते हैं। वे दावा करते हैं कि लोकतंत्र को सचेत किया जाए ताकि वास्तविकता में सुनिश्चित रहे। दूसरी ओर भाजपा और अन्य सत्ता पक्ष इस बात को जोर देते हैं कि पुरानी गलतियों को न दोहराएं। नए लोकतंत्र के नींव को मजबूत रखने की जरूरत है कि चुनाव आयोग को नए विरोधी दल केवल नहीं चुनावी असफलताओं को ध्यान में रखते हुए आरोप लगा रहे हैं। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब जनता चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा करे और मतदाता अपने अधिकारों को जानें और चुनाव आयोग को सुप्रसिद्ध और भूमिका इसमें निर्णायक होती है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्षता की नींव है। सीएलए, वोटिंग मशीन के निष्पक्षता को लेकर चल रहे मतदानों के बीच तथ्य-आधारित बहस जारी है। लोकतंत्र की नींव को मजबूत हो। इस पुरे तर्क-वितर्क के अंत में आम मतदाता की छवि भी ध्यान में रखनी होगी। वह अपने क्षेत्र में निष्पक्ष,

[illegible]

मुत्का ने अपने भारत दौर के बीच दारुल उलूम देवबंद पहुंचकर व वबंदी मसलक से जुड़े दारुल उलूम क उलेमा, छात्रों और अफगान छात्रों के मिकर केवल अपनी अतिवादी न्यायिक प्रतिबद्धता ही नहीं दोहराई बल्कि उन्होंने दिल्ली में ही आयोजित अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में

लालाओं को प्रवेश न देकर भी यह सोच कर दिया कि महिलाओं के प्रति सच विचार के लोग कितनी हिष्णुता का भाव रखते हैं। परन्तु धैर्य है कि भाजपा सरकार वंदे मातरम न का विरोध करे व इसे हाराम का लाली विचारधारा व इसके प्रभावों को तो गले से लगाती है। स्वरागत में लाल कालीन बिछाती परन्तु काँग्रेस पर वंदे मातरम गिराधी का आरोप मढ़ती है। परन्तु जब सच सिंधधान सभा में इस गीत को अपनाने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाजपा बगलों झाँकने लगती है ? तं देश को बेरोजगारी व महंगाई से बुरी जुझ रहा है। डॉलर के मुकाबले एक की कीमत रसतल तक पहुँच है। 2012-13 के मध्य जब भारत के मुकाबले भारतीय रुपये कीमत 60-68 के बीच लुढ़क रही उस समय नरेंद्र मोदी ने दूधिए काकार पर कड़ा प्रहार करते हुये कोणक के रहमायी मुला मुलुसुया पर है, टर्मिनल स्टेज पर है और इसे तुरंत स्टॉप की जरूरत है। उसी समय ये जोर देकर यह भी कहा था कि ये की गिरावट से प्रधानमंत्री की मतगति गिरती है, क्योंकि रुपया केवल का दुकड़ा नहीं, बल्कि देश की श्रष्ट से जुड़ा होता है। उस समय मोदी से तत्कालीन यूपी ए सरकार की

करके नाकामी करार दिया था।
 १० के करीब पहुँच चुकी है।
 १० के करीब में इसपर चर्चा होगी।
 २० असल मोदी सरकार ने
 तातकाल देश का साम्प्रदायिक
 धुवीकरण करने में ज़ोर रख
 करके चुनावों के समय
 शरों में और भी तेजी आ जात
 अश्वर्य में है स्वतंत्रता का
 करण राष्ट्रपान का जो विरोध
 ,गांधी की हत्या पर ज़रन मन
 इयाँ बांटने वाले, भारतीय सँवित
 न पचा पाने वाले लोग आज
 पाने के महा वेडी शास्त्रि तरि
 की बलाद देशभक्त व ध
 भरक्षक ' बनने की कोशिश
 , और देश के स्वतंत्रता का
 णी भूलने का निर्माण करि
 न धूमिल न अजोती की या
 ने वाली कांग्रेस को वेद मा
 प धी को की मुस्लिम परस्
 पा को परस्त्र बातकर मुद्रा प्र
 र महगाई बेरोजगारी जैसे मु
 य्यान भटकने की कोशिश
 , या तद्विना संघर्ष में वेद म
 दुई चर्चा की नहलितकर एक
 भटकने की ऐसी ही एका
 जसमें वेद मातरम को लेकर भ
 और नीतपत का अंतर साफ
 ट।

निर्मल रानी

सुशील वर्मा को भाजपा जिला सचिव बनाया गया



मीरा भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा भायंदर में सराहनीय कामो को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक नरेन्द्र मेहता के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष दिलीप जैन के मार्गदर्शन में सुशील वर्मा को हजरत जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया उनके साथ मे रहे राहुल वर्मा, अनीता दीक्षित, हरीश रावत, संजय सोनार, हरीश उपस्थित रहे।

फिलिप मॉरिस इंडिया ने साल 2025 में अवैध सिगरेट के व्यापार को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया मुंबई। भारत में अवैध सिगरेट का व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था और जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए फिलिप मॉरिस इंडिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीएम इंडिया) ने खुफिया जानकारी का आधार पर कार्रवाई और नीतियों की मदद से अपनी कोशिशें तेज की हैं। संगठन ने खुफिया जानकारी की मदद से पता लगाया कि प्रतिबंधित सिगरेट का कारोबार कहाँ से चलता है तथा यह कितना फैला हुआ है। साथ ही, पारदर्शिता, कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने तथा विश्व के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में उद्योग जगत और सरकार के बीच बातचीत को बढ़ावा दिया। ये कोशिशें स्पलाई चेन को विश्वसनीय बनाए रखने तथा अवैध सिगरेट को देश में आने से रोकने के लक्ष्यों में मदद करने की पीएम इंडिया की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती हैं। यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में अवैध सिगरेट का कारोबार बहुत अधिक फैला हुआ है। इसके अलावा, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डेटा में सामने आया है कि इसमें से एक तिहाई जन्ती उत्तर-पूर्व के क्षेत्र से हुई है, जो अपनी खुली सीमाओं के कारण तस्करी का सबसे बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में 20 प्रतिशत, तमिल नाडु में 13 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 9 प्रतिशत अवैध सिगरेट बरामद हुए हैं। इससे साफ होता है कि तटीय और समुद्री मार्गों से तस्करी बढ़ रही है।

सफाई कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर नागपुर विधानसभा पर मोर्चा 12 दिसंबर को मुंबई। महाराष्ट्र में मुंबई मनपा और नागपुर मनपा सहित विभिन्न सरकारी विभागों के सफाई कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस की ओर से नागपुर विधानसभा पर आगामी 12 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे मोर्चा निकाला जाएगा। प्रेस को जारी किए गए एक विज्ञापित में अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के 1995 के आदेश के निर्णयों के आधार पर ठेकेदारी प्रथा न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए ठेका पद्धति भगाओ, सफाई कामगार वारस हक बचाओ नामक अभियान शुरू किया गया है। बता दें कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई आंदोलन और बैठकें आयोजित की गईं। 8 (आठ) बार विधानसभा और विधान परिषद में विधायकों के माध्यम से प्रलंबित मांगों पर चर्चा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा उक्त मुद्दों पर आश्वासन दिया गया है। किंतु इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। इस कारण महाराष्ट्र के हजारों सफाई कर्मचारी परेशान हैं। जिसके कारण उपरोक्त मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर काग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद भाई परमार के नेतृत्व में नागपुर विधानसभा पर 12 मार्च की सुबह 11 बजे मोर्चा निकाला जाएगा।

एक्सिस म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड मुंबई/पटना। भारत की अग्रणी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने आज एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक ओपन-एंडेड फंड ऑफ फंड्स स्कीम है, जो गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की यूनिट्स में निवेश करेगी। नया फंड ऑफर 10 दिसंबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 22 दिसंबर 2025 को बंद होगा। एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड निवेशकों को एक ही निवेश के जरिए सोने और चांदी झु दुनिया भर में पहचाने जाने वाले दो वैल्यू स्टोर झु के परफॉर्मंस में हिस्सा लेने का एक आसान और पारदर्शी तरीका देता है। यह स्कीम मुख्य रूप से गोल्ड एक्ज़र और सिल्वर एक्ज़र की यूनिट्स में निवेश करेगी, और दोनों कमेडिटीज को संतुलित एलोकेशन देगी। इस नए फंड के लॉन्च पर बोलते हुए, एक्सिस एएमसी के एमडी और सीईओ श्री बी. गोपकुमार ने कहा: सोना और चांदी ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्थिरता के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करते रहे हैं और पोर्टफोलियो को विविधता देने में सहायता करते हैं।

तेलंगाना में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगा गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप मुंबई/पटना। भारत के सबसे बड़े और सबसे विविध एंटीबिजनेस में से एक, गोदरेज एग्रीवेट की सहायक कंपनी, क्रीमलाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो गोदरेज जर्सी ब्रांड नाम के तहत उत्पाद बेचती है, ने आज तेलंगाना राज्जित ग्लोबल समिट 2025 के दौरान तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। कंपनी 40 एकड़ में अत्याधुनिक डेयरी प्रोसेसिंग सुविधा स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस नए निवेश के साथ, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की राज्य में विभिन्न व्यवसायों में कुल निवेश योजना अब 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

जिला परिषद पालघर द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों की जिलास्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न

पालघर(उत्तरशक्ति)। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता बुधवार 10 दिसंबर 2025 को आर्यन हाई स्कूल मैदान में अत्यंत उत्साहपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। जिले के 16 विद्यालयों के कुल 236 दिव्यांग विद्यार्थियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में जोशपूर्ण सहभागिता दर्शाते हुए अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉ. इंद्रानी जाखड़ के हाथों किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी सचिन कवटे, पुलिस उपनिरीक्षक प्रभा राऊल, जिला कार्यक्रम अधिकारी व्यंकटराव हुंडेकर सहित अन्य मान्यवर उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनलकर के नियोजनानुसार आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने मार्च पास कर आतिथियों को सलामी दी। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा क्रीड़ा ज्योति प्रज्वलित कर प्रतियोगिताओं का औपचारिक शुभारंभ किया गया। खिलाड़ियों ने मान्यवरों की उपस्थिति में क्रीड़ा शपथ भी ली। खेल प्रतियोगिता में दौड़, रनिंग लॉन्ग जंप, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, गोला फेंक, स्पोर्ट बॉल थ्रो जैसे विभिन्न खेलों का समावेश था, जिनमें बच्चों ने पूरा दमखम दिखाते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उद्घाटन समारोह में जिलाधिकारी डॉ. इंद्रानी



जाखड़ ने बोलते हुए कहा कि सेस फंड के माध्यम से अंतिम घटक तक पहुंचने वाला यह उपक्रम अत्यंत प्रशंसनीय है। दिव्यांग बच्चों के शिक्षक विशेष सराहना के पात्र हैं। चुनौतियों पर मात देकर मैदान में उतरना ही इन बच्चों की वास्तविक सफलता है। ऐसी प्रतियोगिताएँ उनकी क्षमताओं को नई दिशा देती हैं

महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी युनियन के जक्कार तहसील अध्यक्ष पद पर भाग्येश ढोले निर्वाचित



पालघर(उत्तरशक्ति)। पंचायत समिति जक्कार में आयोजित महाराष्ट्र राज्य जिला परिषद कर्मचारी युनियन की चयन सभा में भाग्येश ढोले को सर्वसम्मति से जक्कार तहसील अध्यक्ष चुना गया। जिला अध्यक्ष सुनील अहिरे (नाना) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपाध्यक्ष पद के लिए मंजुषा वाघ, सचिव पद के लिए तुषार फालके व कार्याध्यक्ष पद के लिए प्रवीण चौधरी को भी चुना गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अहिरे ने बताया कि संगठन

कोटपा उल्लंघन करने वालों से वसूल किये गये 3,750 का दंड

पालघर(उत्तरशक्ति)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जिला अस्पताल पालघर, मनोर पुलिस स्टेशन तथा मराठवाड़ा ग्रामीण विकास संस्था, छत्रपति संभाजीनगर के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार 9 दिसंबर 2025 को मनोर टेन नाका क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण अभियान चलाया गया।

इस विशेष अभियान का संचालन जिला शल्य चिकित्सक डॉ. रामदास मराठ और पुलिस निरीक्षक रणवीर बायस के मार्गदर्शन में किया गया। अभियान के दौरान तंबाकू नियंत्रण अमलबजावणी पथक ने कोटपा 2003 की धारा 4, धारा 6(अ) और धारा 6(ब) का उल्लंघन करने वाले पान-टपरी धारकों एवं व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए कुल 3,750 रुपए का दंड वसूल किया। इस

और समाज के लिए प्रेरणादायी बनती हैं। जिला प्रशासन ऐसे उपक्रमों को और व्यापक बनाने हेतु कटिबद्ध है। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रतियोगिताएँ दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके सामाजिक विकास को सशक्त बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिला परिषद भविष्य में भी ऐसे उपक्रमों को प्राथमिकता देती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान कर्णबधिर एवं मूकबधिर विद्यार्थियों की पूर्ण आयोजित स्पर्धाओं के विजेताओं को भी मान्यवरों के हाथों पुरस्कार प्रदान किये गये। कार्यक्रम का प्रास्ताविक डॉ. प्रकाश हसनलकर ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी खेल प्रतियोगिता के साक्षी बने।

मनोर में चलाया गया तंबाकू नियंत्रण अभियान



अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा शैक्षणिक संस्थानों के

ब्रेव मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजाराम देवासानी को मिली डाक्टर आफ मार्शल आर्ट की उपाधि

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी के ब्रेव मार्शल आर्ट एसोसिएशन के संस्थापक/अध्यक्ष ग्रेड मास्टर राजाराम लक्ष्मीनारायण देवासानी को साउथव्हेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लोबल कार्डसिल फार प्रोफेशनल एजुकेशनल मिशन द्वारा डाक्टर आफ मार्शल आर्ट की उपाधि से फिल्म अभिनेता चिन्नी के हाथों मानद डॉक्टरेट उपाधि का प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि ठाणे जिले के साथ भिवंडी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में कराटे के माध्यम से 4 वर्ष के बच्चों से लेकर 70 वर्ष के नागरिकों को सेल्फ सुरक्षा की शिक्षा देने का कार्य पिछले 27 वर्षों से देने के सराहनीय कार्यों को



देखते हुए साउथव्हेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा चेन्नई के मशहूर रामाडा होटल के फंक्शन हाल में आयोजित कार्यक्रम में डाक्टरेड की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। राजाराम देवासानी को डाक्टर की उपाधि मिलने पर उनके शुभचिंतकों में अशोक देवासानी ,

आचार्य सूरजपाल यादव भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी में नशीली दवाओं और गुटखा की बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है जिसको लेकर कई शिकायतें भी की जा रही हैं वहीं भिवंडी पूर्व विधानसभा के विधायक रईस शेख ने नागपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि भिवंडी शहर गुटखा तस्करी का हब बनता जा रहा है। बता दें कि मंगलवार को विधानसभा में भिवंडी शहर में गुटखा तस्करी का मुद्दा उठाते हुए बताया गया कि इस समय भिवंडी गुटखा तस्करी का हब बनता जा रहा है और गुजरात से आने वाला गुटखा भिवंडी से बांटा जा रहा है जिसके चलते भिवंडी में गोदाम का



धंधा फल-फूल रहा है इसके लिए इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। इसी तरह भिवंडी के पोर्गांव में गुटखा फैक्ट्री मिली थी लेकिन अपराधी जमानत पर बाहर हैं। विधायक रईस शेख ने सदन में मांग की है कि भिवंडी में गुटखा

माफिया की तस्करी पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार एक टाक्स फोरस बनाए। क्योंकि गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले कानून कमजोर हैं इसलिए उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती है। रईस शेख द्वारा उठाये गये सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुटखा का

5 किलो सोना चोरी मामले में एक चोर हिरासत में, अन्य फरार चोरों की तलाश जारी

कल्याण (उत्तरशक्ति)। सिद्धेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन से 5.50 करोड़ रुपये का 5 किलो सोने और आभूषण चोरी होने की घटना की रेलवे की अनेकों एजेंसी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस चोरी मामले में एक चोर सोलापुर से हिरासत में लिया गया है अन्य 5 संदिग्ध चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। इस घटना को पूर्व नियोजित माना जा रहा है। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव निवासी अभयकुमार जैन 7 तारीख को सोलापुर से लौट रहे थे, कल्याण के बीच उनकी दो ट्रॉली बैग में रखे 5



किलो सोने और आभूषण चोरी हो गए। जैन ने कल्याण जीआरपी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई उसके बाद रेलवे पुलिस ने तीन टीम बनाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज, यात्रियों और

रेलवे स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह चोरी पूर्व नियोजित और संगठित गिरोह द्वारा की गई है। फिलहाल इस मामले में एक एक चोर को हिरासत में लिया गया है अन्य 5 लोगो की तलाश जारी है।

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति

* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा

*प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्द

उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।

पत्राचार कार्यालय :

उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)

मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्ल्यू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल ऑटफ हिल वडाला, मुंबई-37

मो.- 9554493941

email ID- uttarshaktinews@gmail.com

प्रजापति

फॅब्रीकेशन अॅण्ड गिल वर्क्स

PRAJAPATI

FABRICATION & GRILL WORKS

MANUFACTURERS OF

COMPOUND GATES, MS GRILLS, WATER TANKS, ROLL SHUTTER, COLLAPSIBLE DOOR & ALLUMINIUM SLIDING WINDOW

SHOP NO. 101, SAVERA CHS., LAST BUS STOP, VEERA DESAI ROAD, ANDHERI (W), MUMBAI-400053. GST No. : 27ANKPP6297R12P

